भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2007

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है।

22 माघ, 1947 (शक)

मध्य प्रदेश में सीएससी का संचालन

2007. श्रीमती संध्या रायः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. मध्य प्रदेश के भिंड-दतिया लोक सभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें हाई-स्पीड इंटरनेट/फाइबर से जुड़ी हुई हैं और केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया, भारतनेट और सीएससी 2.0 योजनाओं के अंतर्गत कितने कार्यरत सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और स्कूलों/कॉलेजों को डिजिटल लैब/वाई-फाई प्रदान किया गया है;

ख. वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

ग. क्या सरकार भिण्ड-दतिया में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास केन्द्रों, स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केन्द्रों और बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

घ. यदि हां, तो कितने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और कितने स्टार्ट अप्स को सहायता प्रदान की जाएगी और इन पहलों के अंतर्गत कितने नए रोजगार सृजित होने की संभावना है; और

ङ. उक्त पहलों के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ)** मध्य प्रदेश के भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 742 ग्राम पंचायतों(जीपी) को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। भारतनेट के माध्यम से लगभग 90 स्कूलों/कॉलेजों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

डिजिटल भारत निधि की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 31.12.2025 तक मध्य प्रदेश को 6533.29 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में सीएससी 2.0 परियोजना के अंतर्गत सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गए हैं। सीएससी 2.0 परियोजना 31.03.2024 को पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों सहित कार्यात्मक सीएससी का राज्य और जिलावार विवरण https://csc.gov.in/ वेबसाइट **पर उपलब्ध है**।

सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गवर्मेंट टू सिटिज़न (जी2सी) और बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) सेवाएं शामिल हैं। सेवाओं की सूची https://csc.gov.in/ पर दी गई है**।**

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है, जिसे सरकार द्वारा सूचना,

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और संबंधित गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है।
वर्तमान में, नाइलिट अपने स्वयं के 56 केंद्रों और 700 से अधिक प्रत्यायित प्रशिक्षण भागीदारों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ-साथ आईईसीटी क्षेत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए 9,000 से अधिक सुविधा केंद्रों का संचालन करता है।

नाइलिट ने डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों (डीएलसी) पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के भिंड में अपने 12 सुविधा केंद्र और दतिया जिलों में 08 सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। पिछले 3 वर्षों में, इन जिलों में नाइलिट के डीएलसी पाठ्यक्रमों में 3000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी डोमेन में **स्टार्टअप इकोसिस्टम** को सुदृढ़ करने हेतु, एमईआईटीवाई ने प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। 2019 में शुरू की गई टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स (**टीआईडीई 2.0) योजना** के अंतर्गत, देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में स्थित 51 चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, एमईआईटीवाई ने लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को उन्नत बनाकर टियर- II और टियर- III शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स **(जेनेसिस) योजना** शुरू की है ।इसके अलावा, एमईआईटीवाई ने नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में कई डोमेन-विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र **(सीओई)** और थीम-आधारित इन्क्यूबेसन केंद्रों का संचालन किया है। ये केंद्र ईएसडीएम, फिनटेक, मेडटेक, एग्रीटेक, आईओटी और अन्य उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को लक्षित सहायता प्रदान करते हैं।

******